नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

10वीं-12वीं का शानदार परिणाम

बेटियों ने किया टॉप

73.42 प्रतिशत रहा 10वीं की परीक्षा परिणाम

76.01 प्रतिशत रहा 12वीं परीक्षा का परिणाम

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 15 अप्रैल. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किए हैं. इस साल का परिणाम पिछले 16 वर्षों में सबसे शानदार रहा है. प्रदेश में एक बार फिर बेटियों ने अपना दबदबा कायम रखा है.

10वीं की परीक्षा में लगभग 9 लाख 7 हजार छात्र शामिल हुए थे, जिनका कुल पास प्रतिशत 73.42 रहा. वहीं 12वीं की परीक्षा में करीब 7 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 76.01 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं. वहीं इस बार सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहा है.

प्रतिभा सोलंकी
कक्षा 10वीं टॉप

खुशी राय
कक्षा12वीं टॉप

चांदनी विश्वर्मा
कक्षा12वीं टॉप

10वीं के टॉपर

1. प्रतिभा सिंह सोलंकी, पन्ना - 499 अंक
2. अमेय गुप्ता और अक्षरा चौधरी (संयुक्त रूप से) - 498 अंक
3. हिमांशी (भोपाल)- 497 अंक

12वीं के टॉपर

1. खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा, भोपाल- 494 अंक
2. रिमझिम करोठिया, ग्वालियर- 491 अंक
3. अंकुर यादव - 489 अंक

सीबीएसई बोर्ड 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं सेशन - 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99 प्रतिशत है, जबकि लड़कों का रिजल्ट 92.95 प्रतिशत दर्ज किया है. ट्रांसजेंडर छात्रों ने भी इस बार 91.30 प्रतिशत रिजल्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है. 99.75 प्रतिशत के साथ त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट बेस्ट रहा है. कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in और उमंग एप पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स इस साल सीबीएसई बोर्ड 10वीं की सेशन 1 परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिनका रिजल्ट जारी किया गया है. उमंग और डिजिलॉकर सहित सभी सरकारी पोर्टल सक्रिय हो चुके हैं और एक फ्लैश संदेश के जरिए परिणामों की घोषणा की गई. छात्र अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी मार्कशीट और प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं.

सीबीएसई में ये रहे प्रदेश में टॉपर

भोपाल रीजन में इस साल 10वीं की परीक्षा के लिए 1 लाख 15 हजार 889 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा के परिणामों में भोपाल की सान्वी झा ने भोपाल क्षेत्र से 99.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. भोपाल के सेज इंटरनेशनल स्कूल कोलार के छात्र आस्तिक पाठक ने सीबीएसई 10वीं में 99.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. वहीं सागर पब्लिक स्कूल की प्रांशी तिवारी ने 98.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. श्याम खंडेलवाल- 97 प्रतिशत, प्रखर दुबे- 97 प्रतिशत, पुरंजय पराशर-96.8 प्रतिशत और इनाक्षी गुप्ता को 96 प्रतिशत अंक मिले हैं. शाजापुर के तनिष्क शर्मा ने 98.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. वहीं भोपाल की नम्रता सक्सेना को 98.2 प्रतिशत मिले हैं.

वंदे मातरम को लेकर दो महिला पार्षदों पर एफआईआर

नव भारत न्यूज

इंदौर. नगर निगम बजट सत्र में वंदे मातरम के मुद्दे पर बुधवार को पुलिस ने दोनों पार्षदों पर एफआईआर दर्ज कर ली. इसके पूर्व पुलिस ने दो पार्षदों को अलग-अलग दिन बुलाकर बयान दर्ज किए है. इसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. एमजी रोड पुलिस ने नगर निगम बजट बैठक में वंदे मातरम के मुद्दे पर मुस्लिम महिला पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान पर एफआईआर दर्ज कर ली है. फौजिया ने वंदे मातरम गाने को इस्लाम के विरुद्ध कहा था, वही रुबीना खान ने बहस में अपशब्दों का प्रयोग कर तुम्हारे बाप में दम हो तो वंदे मातरम बुलवा कर दिखाओ? चुनौती दी थी. उक्त मामले में भाजपा पार्षदों ने एमजी रोड थाने पर आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. भाजपा पार्षदों के आवेदन पर पुलिस ने सोमवार को फौजिया शेख और मंगलवार को रुबीना खान के बयान लिए थे. एडीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पार्षदों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (1) में एफआईआर दर्ज की गई है.

अनुराग जैन सीएस का पद छोड़ेंगे, नीति आयोग जाएंगे

- प्रदेश में टॉप लेवल पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव होगा
- डॉ. राजेश राजौरा हो सकते हैं नए मुख्य सचिव

कन्हैया लोधी

भोपाल, 15 अप्रैल. मप्र के प्रशासनिक गलियारों में अगले कुछ दिनों में बड़ा घटनाक्रम हो सकता है. प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन पद छोड़ सकते हैं और दिल्ली की राह पकड़ सकते हैं. वे नीति आयोग में बतौर सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं. जैन के पद छोड़ने के बाद डॉ. राजेश राजौरा प्रदेश के मुख्य सचिव बन सकते हैं.

मिले संकेतों के मुताबिक अनुराग जैन अगले कुछ दिनों में ही मौजूदा दायित्व से मुक्त हो सकते हैं. इस संबंध में उच्च स्तर पर सहमति बन गई है. बताया जा रहा है जैन को

इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से ही मिला है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है. इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी मौखिक सहमति दे दी है. अब केवल औपचारिकता बाकी है. दरअसल प्रदेश का मुख्य सचिव बनने से पहले अनुराग जैन केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, वे प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे समय तक रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुड लिस्ट में जिन अफसरों को शुमार किया जाता है, उनमें जैन का नाम भी शामिल है.

वित्त के विशेषज्ञ हैं अनुराग जैन

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1989 बैच के अधिकारी अनुराग जैन को वित्त से जुड़े विषयों का बड़ा जानकार माना जाता है. तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय वे एसीएस वित्त की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. यही वजह है कि उन्हें नीति आयोग में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है.

ईडी ने 160 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले में 159.51 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. ईडी ने बुधवार को यह जानकारी दी है. जांच में सामने आया है कि अवैध खनन का यह पूरा खेल अनूप माजी उर्फ लाला के नेतृत्व वाले एक गुट द्वारा चलाया जा रहा था. पश्चिम बंगाल की कुछ कंपनियों ने जानबूझकर अवैध रूप से निकाला.

सुधार के नाम पर धार्मिक परंपराओं को कमजोर नहीं कर सकते

नई दिल्ली, 15 अप्रैल. केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़े ऐतिहासिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.

चौथे दिन की बहस में मंदिर प्रबंधन का पक्ष रखने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने कहा कि यह कोई सामान्य सार्वजनिक

स्थान नहीं है, बल्कि भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी स्वरूप का मंदिर है, जहां परंपराओं का विशेष महत्व है. मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा फिर से गरमा गया कि क्या धार्मिक परंपराओं को आधुनिक संवैधानिक अधिकारों के साथ संतुलित किया जा सकता है। अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे—एक ओर परंपरा और आस्था का पक्ष, तो दूसरी ओर समानता और अधिकारों की बात ।यह मामला लंबे समय से चर्चा में है. क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि धर्म, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे तय किया जाए.

भारतीय मूल की अमेरिकी जज को हटाने का फैसला

नई दिल्ली. ट्रंप प्रशासन ने भारतीय मूल की इमिग्रेशन जज रूपल पटेल को उनके पद से हटाने का फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई तब की गई जब एक हाई प्रोफाइल डिपोर्टेशन केस में जज ने एक फिलिस्तीन समर्थक छात्र के हित में फैसला सुनाया था. पटेल उन छह इमिग्रेशन जजों में से एक थीं जिन्हें शुक्रवार को जीओपी प्रशासन ने नौकरी से निकाल दिया. पटेल को जनवरी में दिए गए एक फैसले के बाद हटाया गया, जिसमें उन्होंने रूमेसा ओजतुर्क को डिपोर्ट करने का कोई कानूनी आधार नहीं पाया था. ओजतुर्क तुर्किये में जन्मी एक छात्रा थी, जिसका वीजा तब रद्द कर दिया गया था, जब उसने एक छात्र अखबार में फिलिस्तीनी मुद्दों पर अपने विश्वविद्यालय की आलोचना की थी.